आकाशवाणी केन्द्र शिमला
17.08.2017 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

उद्योग

आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने जीएसटी व्यवस्था के तहत हिमाचल समेत कुछ अन्य पहाड़ी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक जीएसटी में छूट की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समिति की कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। उद्योगों को ये सुविधा रिफंड के रूप में मिलेगी और इसका उद्देश्य पहाड़ी राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है। इससे विभिन्न राज्यों में 4 हजार 2 सौ 84 पात्र इकाईयों को लाभ मिलेगा। जीएसटी से पहले इन इकाईयों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट मिलती थी।

उच्चतम न्यायालय

केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि देश भर में स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियां नियमित करने संबंधी कानून बनाकर जल्दी ही नीतिगत फैसला लिया जायेगा। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान पर विचार किया। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 35वां संस्करण होगा। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है। लोग अपने विचार, दृष्टिकोण और सुझाव माई गोव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा वे टॉल–फ्री नम्बर–एक आठ शून्य शून्य – एक एक – सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश 23 अगस्त तक रिकॉर्ड करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पुलिस कर्मचारियों से बुराई मुक्त समाज बनाने का आहवान किया है। वे आज पालमपुर के समीप डरोह में पुलिस जवानों के 16वें बैच की पासिंग आउट परेड के मौके बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था भंग कर समाज में भय का माहौल पैदा न कर सकें। वीरभद्र सिंह ने नए पुलिस जवानों को अधिक पेशेवर बनने और लोगों से धैर्य के साथ व्यवहार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुलिस आज विभिन्न चुनौतियों का बाखूबी सामना कर रही है जो कि सराहनीय है।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने मंडी ज़िला प्रशासन को कोटरोपी गांव के पास भूस्खलन से बंद राष्ट्रीय राज मार्ग 5 दिन में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। आज अधिकारियों के साथ उन्होंने इलाके का दौरा किया और खोज अभियान का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में इस त्रासदी की पुर्नावृति रोकने के लिए लम्बी अवधि के उपायों पर विचार किया जा रहा है। फारका ने कहा कि जिन लोगों के मकान व जमीन मलबे में दब गए हैं उन्हें जमीन देने के साथ–साथ निर्माण के लिए धन भी दिया जाएगा।

कौल सिंह

स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के अलावा राज्य के डोडरा–क्वार व पांगी जैसे दूर–दराज इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रो को टैलीमैडिसिन सुविधा से जोड़ा जाएगा। लाहौल–स्पीति के काजा में एक समीक्षा बैठक में आज उन्होंने ये जानकारी दी और बताया कि काजा सिविल अस्पताल में टेलीमैडिसिन के माध्यम से 4 हजार 7 सौ 76 मरीजों का ईलाज किया गया है। उन्होंने अस्पताल में एक्सरे मशीन स्वीकृत करने और लोसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक्सरे सुविधा जल्द खोलने का आश्वासन दिया।

टीकाकरण

इधर मीजल्ज–रूबेला टीकाकरण अभियान इस महीने के अतिंम सप्ताह से शुरू हो कर अगले 5 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान 9 माह से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। कांगड़ा ज़िला के एडीएम मस्तराम भारद्वाज ने धर्मशाला में एक बैठक में सभी को आपसी ताल–मेल से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। जिले में 3 लाख 97 हजार से अधिक बच्चों को टीके लगाने का लक्ष्य है। ऊना के एडीएम सुखदेव सिंह ने बताया कि ज़िले में करीब एक लाख 28 हजार बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा।

फसल बीमा

भारत सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी प्रावधानों का यथासंभव सरलीकरण किसानों के हितों के अनुरूप किया गया है। इसमें किसानों को जोखिमों से बचाने और अधिकतम आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं की कमियों को सुधार कर शुरू की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से का प्रीमियम कम किया गया है। इससे किसानों की समझ, फसल क्षेत्र और फसलों का कवरेज बढ़ा है। योजना में किसानों को संपूर्ण बीमित राशि के साथ–साथ पूरे दावे का बिना कटौती अतिशीघ्र समयबद्ध भुगतान हो रहा है।

प्रतियोगिता

सोलन स्थित ठोडो मैदान में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष फुटबॉल प्रतियोगिता कल शुरू हुई। तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में शिमला, सोलन व सिरमौर की 25 टीमे भाग ले रही है। इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को काम के बोझ व तनाव से राहत दिलाना है।